for relaxation of ban orders, instructions have recently been issued to the Army HQrs. to issue letters to all concerned Employment Exchanges explaining the status of the selected SC/ST candidates to enable the latter either to renew the registration or to re-register such candidates, if their names have been deleted from their list.

रक्षा मंत्रालय द्वारा पुस्तकों की खरीद

3810. **श्रीमती वीणा वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय में पुस्तकों की खरीद हेतु क्या मानदंड अपनाये जाते हैं ;

(ख) क्या पुस्तकों की खरीद हेतु गठित की गई समिति में देश के कुछ प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्तियों को शामिल किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय काव्य पुस्तकों की खरीद नहीं करता; और

(घ) क्या सरकार गत दो वर्षों के दौरान खरीदी गई पुस्तकों की सूची सभा पटल पर रखेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सैनिकों के मनोरंजन के लिए पुस्तकों का चयन करने के वास्ते रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक पुस्तक चयन उप समिति का गठन किया है। तथापि पुस्तकों की वास्तविक खरीद और उनकी संख्या का निर्णय पुस्तकों की आवश्यकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर उप समिति द्वारा चयनित पुस्तकों में से संबंधित मुख्यालयों द्वारा किया जाता है।

इस समिति द्वारा सैनिकों के मनोरंजन के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्न-निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाती है :—

(1) पुस्तकें मनोरंजन करने वाली होनी चाहिए।

(2) हल्की पठन सामग्री जिसमें कहानी-किस्से और उपन्यास हों। देशभक्ति भजन और कविताओं वाली पुस्तकें खरीदे जाने की भी सिफारिश की जाती है।

(3) महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्-राष्ट्रीय नेताओं की जीवनियां तथा आत्म-कथाएं।

(4) व्यावसायिक प्रशिक्षण खेल-कूद, सामाजिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान और धर्म के बारे में प्रारम्भिक जानकारी देने वाली पुस्तकें।

(5) रक्षा संबंधी विषयों पर हिन्दी की पुरस्कृत पुस्तकें।

(6) नेशनल बुक ट्रस्ट और इसी तरह के अन्य निकायों द्वारा प्रकाशित पुस्तकें ; और

(7) ऐसी पुस्तकें जिन्हें केन्द्रीय या राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया गया हो।

सैनिकों के लिए निम्नलिखित विषयों वाली पुस्तकों की खरीद करने की सिफारिश नहीं की जाती है :—

(1) ऐसी पुस्तकें जो भिन्न-भिन्न धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाती हों।

(2) विवादास्पद राजनैतिक विषय वाली पुस्तकें।

(3) ऐसी पुस्तकें जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन हो।

(4) अत्यंत तकनीकी विषय वाले प्रकाशन।

(5) विवादास्पद विषयों पर आपत्ति जनक सामग्री वाले प्रकाशन।

(6) ऐसे प्रकाशन जिनसे रक्षा सेवा कार्मिकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(7) अश्लील साहित्य की श्रेणी में आने वाले प्रकाशन।

सैनिकों के लिए अपेक्षित पुस्तकों के अतिरिक्त रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले विभिन्न विभाग और संगठन अपनी

आवश्यकताओं के अनुसार संदर्भ तथा तकनीकी पुस्तकें खरीद रहे हैं। ऐसी खरीद आवश्यकता पर आधारित होती है और इसके लिए कोई केन्द्रीयकृत चयन समिति नहीं है।

पिछले दो वर्षों के दौरान सेना मुख्यालयों और तटरक्षक ने सैनिकों के मनोरंजन के लिए कुल 4984 पुस्तकें खरीदी थीं।

Services conditions of staff in MI Directorate

3811. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Examiners, Assistant Examiners and Packers working in the MI Directorate of Ministry of Defence have time and again represented against the prevaling stagnation with regard to their promotional avenues and further service prospects during the last ten years and if so, the facts thereof;

(b) whether Government have considered their grievances/demands and taken any steps to improve there pay scales and provide more promotional avenues and if so, the details thereof with justification; and

(c) whether Government have taken any initiative to present their case to the Fifth Pay Commission in order to improve their service prospects and pay scales, and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) and (b) Representations were received from Censor Staff prior to setting up of the Fourth Central Pay Commission. Suggestions for upgradation of pay scales and creation of posts in a higher grade were made to the Fourth Central Pay Commission. The recommendations of the Commission for grant of the revised pay scales of Rs. 2000-3500, Rs. 1600-2660, Rs. 1400-2300 and Rs. 775-1025 to the posts of Supervisory Examiner, Examiner, Assistant Examiner and Packer respectively were accepted and given effect to.

(c) The matter regarding further improvement in pay scales etc., falls in the purview of the Fifth Central Pay Commission. Examiners Welfare Association has already forwarded their memorandum accordingly.

US views on the defence requirements of sub continent

3812. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the important points discussed with the U.S. Defence Secretary during his recent visit to New Delhi;

(b) whether Government have found and shift in U.S. views on the culture of violence, defence requirements of the sub continent and active support by Pakistan to terrorist subversionists in J and K and elsewhere in India; and

(c) what were the specific defence matters discussed and what are the agreements made?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI MALLIKARJUN): (a) Co-operation in U.N. Peace keeping establishing a broader Security dialogue, closer ties at the level of civilian defence leadership, between the uniformed Services, and in the field of defence production and research, were some of the important points discussed with U.S. Defence Secretary during his recent visit to New Delhi.

(b) Our respective position on these matters were reiterated by both sides. "A Security Perception Briefing" was also provided to the U.S. Defence Secretary.

(c) An "Agreed Minute" on defence relations between India and the U.S.A. was signed. It provides for Civilian-to-Civilian interaction, Service-to-Service Co-operation and Co-operation in the field of research and development. The